करेंट अफेयर्स राजस्थान

(संग्रह)

जून 2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोनः 8750187501

ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- राज्यस्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का उद्घाटन 3
- राज स्किल, 2022' प्रतियोगिता 3
- मानसरोवर चौपाटी को एफएसएसएआई से मिला 'क्लीन स्ट्रीट फूड हब' का सर्टिफिकेट 3
- उप-तहसील निर्झरना एवं बांदीकुई तहसील में क्रमोन्नत, नवीन उप-तहसील आभानेरी का भी सृजन 4
- पर्यावरण जन-जागृति दौड़ का आयोजन 4
- एनीमियामुक्त राजस्थान के लिये 'शक्ति दिवस' 5
- नवीन उप-तहसील बार तथा टोडरा के सृजन के प्रस्ताव को मंज़ूरी 5
- खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2021-22 में राजस्थान 10वें स्थान पर 6
- अवनी लेखरा ने पैरा-शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड 6
- राजस्थान के 37 आवासीय विद्यालयों को मिला ईट-राईट-स्कूल प्रमाण-पत्र 7
- प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास एवं भूमि पूजन 7
- चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी 7
- वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2022 में संशोधन 8
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में तीन जल वितरण समितियों का गठन 8
- भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक व सिल्वर के पूर्ववेक्षण की तैयारी 9
- पाँच दिवसीय 'हैंडलूम प्रदर्शनी-कम सेल' का शुभारंभ 9
- जयपुर में 'आईस्टार्ट राजस्थान' के तहत हुआ 'ड्रोन एक्सपो-2022' 10
- देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना 10
- राजस्थान के नये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 11
- राजस्थान में लव-कुश वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से होगा आरंभ 11
- सौर कृषि आजीविका योजना (स्काय) के अंतर्गत 1 लाख सोलर पंप होंगे स्थापित 12
- 1 जुलाई से राजकीय कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएँ प्रतिबंधित 12
- जोधपुर व डूँगरपुर ज़िले के 1-1 राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर 13
- एमएसएमई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये करौली ज़िले को मिला देश में दूसरा स्थान 13
- प्रशासन शहरों के संग अभियान 13
- 'मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना' 14
- ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को मिलेंगे रिप्स-2019 के लाभ 14
- यूरेनियम खनन के क्षेत्र में राजस्थान का प्रवेश 15
- मिशन बुनियाद' 15
- फेस्टिवल ऑफ इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ राजस्थान 15
- राजस्थान में बनेगी नई युवा नीति 16

नोट :

राजस्थान

राज्यस्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2022 को राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया एवं खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने जयपुर में सिरसी रोड स्थित अलंकार महाविद्यालय में राज्यस्तरीय सब-जूनियर व जूनियर बालक-बालिका तैराकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रतियोगिता का आयोजन 1 जून से 5 जून तक किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 16 ज़िलों के 325 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
- इस पाँच दिवसीय प्रतियोगिता में शामिल होने वाले 325 खिलाड़ियों में से सब-जूनियर वर्ग में 45 तैराक, जबकि जूनियर वर्ग में 280 तैराक हिस्सा ले रहे हैं।
- इसका आयोजन राजस्थान तैराकी संघ के तत्त्वावधान में किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष अनिल व्यास हैं।

राज स्किल, 2022' प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों ?

2 जून, 2022 को राजस्थान के कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से प्रशिक्षणार्थियों में आपसी प्रतिस्पर्द्धा की भावना बढ़ाकर कौशल में अधिक दक्ष बनाने के लिये 'राज स्किल, 2022' प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- तीन चरणों में होने वाली यह प्रतियोगिता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के प्रशिक्षणार्थियों एवं तकनीकी दक्ष नॉन-आईटीआई युवाओं के लिये अलग-अलग होगी।
- अशोक चाँदना ने बताया कि राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वाधिक लोकप्रिय विद्युतकार, फिटर एवं डीजल मेकैनिक, कोपा एवं स्विंग टेक्नोलॉजी तथा नॉन-इंजीनियरिंग व्यवसायों में ड्रेस मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
- इसी प्रकार तकनीकी रूप से दक्ष नॉन-आईटीआई आम युवाओं के लिये समानांतर श्रेणी में प्रतियोगिता करवाकर उन्हें कौशल प्रदर्शन का मंच उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके अंतर्गत राज्यस्तरीय प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थियों में से प्रत्येक व्यवसाय में पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को राज्यस्तरीय विजेता घोषित कर उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- डॉ. आरुषी मलिक ने बताया कि प्रत्येक स्तर पर भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिया जाएगा तथा ज़िलास्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम चार स्थान एवं संभागस्तर पर प्रथम तीन स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को समारोह आयोजित कर पारितोषिक दिया जाएगा।

मानसरोवर चौपाटी को एफएसएसएआई से मिला 'क्लीन स्ट्रीट फूड हब' का सर्टिफिकेट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने राजस्थान आवासन मंडल की मानसरोवर चौपाटी को 'क्लीन स्ट्रीट फूड हब' का सर्टिफिकेट प्रदान किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- एफएसएसएआई (FSSAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंघल ने विभिन्न मानकों एवं बेंचमार्क में खरा पाए जाने पर मानसरोवर चौपाटी को यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया है।
- 'क्लीन स्ट्रीट फूड हब' टैग दो साल के लिये वैध है और यह उन भोजनालयों को दिया किया जाता है, जो खाना पकाने और गैर-खाना पकाने के क्षेत्रों, साफ-सफाई और कीट नियंत्रण सहित कई मामलों के मानकों पर खरे उतरते हैं।
- एफएसएसएआई के अनुसार टैग से पुरस्कृत होने के लिये स्ट्रीट फूड जॉइंट को निर्दिष्ट मानदंडों के कम-से-कम 80% को पूरा करना होता है।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की यह संस्था देश भर में खाद्य सुरक्षा एवं भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सबसे बड़ी नियामक संस्था है।

उप-तहसील निर्झरना एवं बांदीकुई तहसील में क्रमोन्नत, नवीन उप-तहसील आभानेरी का भी सृजन

चर्चा में क्यों ?

5 जून, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा ज़िले की निर्झरना एवं बांदीकुई उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने तथा आभानेरी को नवीन उप-तहसील बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार संबंधी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने नियमों में शिथिलता देते हुए यह स्वीकृति प्रदान की है।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण में सुगमता होगी।
- क्रमोन्नत तहसील निर्झरना में 3 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त तथा 10 पटवार मंडल व 43 राजस्व ग्राम तथा बांदीकुई में 8 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 26 पटवार मंडल व 123 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। साथ ही, नवीन उप-तहसील आभानेरी में 2 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 6 पटवार मंडल तथा 23 राजस्व ग्राम शामिल होना प्रस्तावित है।
- गौरतलब है कि एक दिन पहले 4 जून को मुख्यमंत्री ने भरतपुर ज़िले के जालूकी, खरैरी, गोपालगढ़ तथा खोह को नवीन उप-तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी थी।
- नवीन उप-तहसील जालूकी में 2 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 8 पटवार मंडल तथा 29 राजस्व ग्राम और नवीन उप-तहसील खरैरी में 3 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 12 पटवार मंडल तथा 50 राजस्व ग्राम शामिल होना प्रस्तावित है।
- इसी प्रकार नवीन उप-तहसील गोपालगढ़ में 4 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 15 पटवार मंडल तथा 60 राजस्व ग्राम एवं नवीन उप-तहसील खोह में 5 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 15 पटवार मंडल तथा 41 राजस्व ग्राम शामिल होना प्रस्तावित है।

पर्यावरण जन-जागृति दौड़ का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

5 जून, 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं अन्य विभागों के सहयोग से सुबह अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग से पर्यावरण जन-जागृति दौड़ का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस, 2022 की थीम 'ऑन्ली वन अर्थ' (Only One Earth) रखी गई।

नोट :

- इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा विशेष थीम 'सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध' रखी गई तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया।
- इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने 'स्टेट क्लाइमेंट चेंज एक्शन प्लान' का विमोचन किया। यह एक्शन प्लान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट घोषणा की अनुपालना में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा आईआईटी मुंबई के सयुंक्त अनुबंध में बनाया गया है।
- इसके अलावा वायु गुणवत्ता निगरानी हेतु प्रयुक्त मोबाइल वैन, ई-वेस्ट संग्रहण हेतु प्रयुक्त वाहनों तथा पर्यावरण जन-जागृति हेतु 'रन फॉर एनवायरनमेंट' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
- यह मोबाइल वैन चलती-फिरती प्रयोगशाला के रूप में कार्यरत होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें विभिन्न स्थानों पर अस्थाई रूप से कुछ दिनों के लिये संचालित कर वहाँ की वायु गुणवत्ता का मापन किया जा सकेगा।
- विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान सरकार तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा Attero रिसाइक्लिंग के सहयोग से डोर-टू-डोर ई-वेस्ट संग्रहण हेतु जागरुकता अभियान चलाकर ई-वेस्ट के संबंध में आमजन को जागरूक किया जाएगा। Attero द्वारा जयपुर शहर में डोर-टू-डोर जाकर ई-वेस्ट एकत्रित किया जाएगा।

एनीमियामुक्त राजस्थान के लिये 'शक्ति दिवस'

चर्चा में क्यों ?

6 जून, 2022 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी ने बताया कि राजस्थान को एनीमियामुक्त करने के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर हर माह के प्रथम मंगलवार को 'शक्ति दिवस' के रूप में आयोजित करेगा।

प्रमुख बिंदु

- इस अभियान के तहत बच्चों, महिलाओं व किशोरियों में एनीमिया की दर कम करने के लिये विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी ।
- 'शक्ति दिवस' आंगनबाड़ी केंद्रों, राजकीय विद्यालयों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उपस्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सीएचसी, डिस्पेंसरी, उपज़िला तथा ज़िला अस्पताल में आयोजित किया जाएगा।
- एनीमिया की स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन की जाँच व एनीमिया का उपचार, आयरन की टेबलेट्स का वितरण, एनीमिया संबंधी जागरूकता तथा व्यवहार परिवर्तन हेतु गतिविधियाँ 'शक्ति दिवस' पर आयोजित की आंगनबाड़ी।
- 'शक्ति दिवस' पर आंगनबाड़ी केंद्रों एवं चिकित्सा संस्थानों में 6 माह से 59 माह तक के बच्चों, 5 से 9 वर्ष तक के विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों, 10 से 19 वर्ष की किशोरी बालिकाओं, 20 से 24 वर्ष की विवाहित महिलाओं, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं में एनीमियामुक्ति के लिये विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।
- इसी प्रकार राजकीय विद्यालयों में अवकाश समाप्ति पर कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों में एनीमियामुक्ति के लिये विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।

नवीन उप-तहसील बार तथा टोडरा के सृजन के प्रस्ताव को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

7 जून, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद ज़िले के बार (तहसील भीम) तथा सवाई माधोपुर ज़िले के टोडरा (तहसील सवाई माधोपुर) को नवीन उप-तहसील बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार संबंधी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने नियमों में शिथिलता देते हुए यह स्वीकृति प्रदान की है।

नोट :

- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण में सुगमता होगी।
- नवीन उप-तहसील बार में 2 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 7 पटवार मंडल तथा 36 राजस्व ग्राम तथा नवीन उप-तहसील टोडरा में 3 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 11 पटवार मंडल और 51 राजस्व ग्राम शामिल होंगे।
- गौरतलब है कि 6 जून, 2022 को मुख्यमंत्री ने सीकर ज़िले की पाटन तथा रींगस उप-तहसील को भी तहसील में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी।

खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2021-22 में राजस्थान 10वें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

7 जून, 2022 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) जारी किया, जिसमें राजस्थान को 10वाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- मंडाविया ने एफएसएसएआई द्वारा ईट राइट रिसर्च अवार्ड्स और ग्रांट्स फेज-II, ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज फेज-III, स्कूल स्तर पर एक प्रतियोगिता सहित विभिन्न नवीन पहलों की शुरुआत की।
- खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2021-22 में 17 बड़े राज्यों के बीच तमिलनाडु 82 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि गुजरात 77.5 अंकों के साथ दूसरे और महाराष्ट्र 70 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
- बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान 50.5 अंकों के साथ 10वें स्थान पर है।
- छोटे राज्यों में गोवा ने अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी, जबकि मणिपुर और सिक्किम ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने शीर्ष तीन रैंक हासिल की।
- गौरतलब है कि राज्यों को खाद्य सुरक्षा के पाँच मानकों- मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तीकरण पर आँका गया है।
- खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2018-19 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाना था। नागरिकों के लिये सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रेरित करने के लिये भी यह कदम उठाया गया था।

अवनी लेखरा ने पैरा-शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड

चर्चा में क्यों ?

7 जून, 2022 को भारत की स्टार पैरा-शूटर टोक्यो पैरालंपिक्स चैंपियन अवनी लेखरा ने फ्राँस के चेटियारो में पैरा-शूटिंग वर्ल्ड कप में आर2 महिला 10 मीटर एयर राइफल में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता।

प्रमुख बिंदु

- जयपुर की 20 साल की अवनी ने महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 स्पर्धा में 250.6 अंकों के साथ यह गोल्ड जीता है। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स में जगह बना ली है।
- अवनी ने 249.6 के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
- गौरतलब है कि अवनि ने पिछले साल अगस्त में टोक्यो पैरालंपिक में एसएच 1 वर्ग में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन एसएच 1 स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता और पैरालंपिक में एक से अधिक पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट हैं।

नोट :

राजस्थान के 37 आवासीय विद्यालयों को मिला ईट-राईट-स्कूल प्रमाण-पत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के 37 आवासीय स्कूलों को ईट-राईट-स्कूल के तौर पर मान्यता प्रदान करते हुए सर्टिफिकेट जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ राजस्थान के 37 राजकीय आवासीय विद्यालयों को यह प्रमाण-पत्र मिला है।
- इन विद्यालयों को उच्च गुणवत्तायुक्त, हाईजेनिक एवं पौष्टिक खाने के सभी मानक पूरे करने के आधार पर यह प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं।
- कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, नाचना (जैसलमेर), मूंगरा (बाड़मेर), नीठार (भरतपुर), भीनमाल (जालौर), कुचामन (नागौर), नीडच (राजसमंद), नंदीशमा (उदयपुर), बौराज (जयपुर), खैतरली (पाली), टिब्बी (हनुमानगढ़), दौसा, बौंली (सवाईमाधोपुर), टोडारायसिंह (टोंक), घड़साना (गंगानगर), पोगल (बीकानेर), जावल (सिरोही), डूँगरपुर, राजगढ़ (चूरू), मांदड (सिरोही), हसंई (धौलपुर), अजमेर, शाहबाद (बारां), चाकसू (जयपुर) तथा चौमाला (झालावाड़) को ईट-राईट-स्कूल का दर्जा मिला है।
- इसी प्रकार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खैरोदा (उदयपुर), चारभुजा (राजसमंद), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासकृपाल नगर (अलवर), राजपुरबड़ा (अलवर), बरनाला (सवाई माधोपुर), नाहरगढ़ (चित्तौड़गढ़) तथा अनूपपुरा जालसू (जयपुर) को ईट-राईट-स्कूल का दर्जा मिला है।
- इनके अलावा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतारण (पाली), ब्राह्मणों की सरीरी आसींद (भीलवाड़ा), जायल (नागौर), नरोलीडांग (करौली), मौलासर (नागौर) तथा खोड़वाड़ा ईटावा (कोटा) को ईट-राईट विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है।

प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास एवं भूमि पूजन

चर्चा में क्यों ?

12 जून, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद ज़िले की खमनोर तहसील के बिल्ली की भागल गाँव में प्रदेश के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भूमिपूजन और शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस सेंटर के लिये पहले चरण में 30 करोड़ रुपए देने की तथा नाथद्वारा में राज्य सरकार की ओर से गायत्री परिवार को 5 हेक्टेयर ज़मीन नि:शुल्क देने की घोषणा की।
- समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मेडिटूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान का पहला योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है।
- इस वेलनेस सेंटर में आयुर्वेदिक औषधियों, योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि से लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के और भी सेंटर अन्य स्थानों पर खोले जाएंगे।
- इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने कहा कि इस वेलनेस सेंटर में आने वाले हर व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण मिलने के साथ ही यहाँ मेडिकल टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही ऐसी आधारभूत संरचनाओं से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति मिलेगी।

चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी

चर्चा में क्यों ?

14 जून, 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित 'चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी' का उद्घाटन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित चारकोल से उकेरी गई माउंट आबू की नक्की झील, गुरु शिखर के नैसर्गिक सौंदर्य, किले, महलों के साथ-साथ पोर्ट्रेट्स, झरोखे आदि के चित्रों का अवलोकन करते हुए इन्हें सुंदर कलाकृतियाँ बताया।
- पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने बताया कि केंद्र की ओर से माउंट आबू में गत दिनों आयोजित चारकोल चित्रांकन कैंप में 24 कलाकारों द्वारा चारकोल से सुंदर चित्रों का सृजन कैनवास पर किया गया। इन चित्रों को यहाँ राजभवन में आयोजित 'चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी' में प्रदर्शित किया जाएगा।
- इसके अलावा राज्यपाल ने पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा आयोजित तीनदिवसीय 'भक्ति उत्सव' का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।
- 'भक्ति उत्सव' में भक्ति रस से सराबोर कबीर वाणी, भजन और सूफी संगीत की कलाकारों द्वारा भावपूर्ण प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2022 में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

15 जून, 2022 को राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2022 के तहत वरिष्ठ नागरिक की उम्र 65 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष या उससे अधिक आयु पढ़ी जाने के संशोधित आदेश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के अंतर्गत 18 हज़ार वरिष्ठ नागरिकों को रेलमार्ग और 2 हज़ार वरिष्ठ नागरिकों को वायुयान मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। कुल मिलाकर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस बार 20 हज़ार वरिष्ठ नागरिक देश भर के तीर्थ स्थलों की नि:शुल्क यात्रा करेंगे।
- यात्रा के लिये पात्र व्यक्ति का राजस्थान का मूल निवासी और 60 वर्ष से अधिक आयु का होना आवश्यक है। आयु की गणना 1 अप्रैल, 2022 को आधार मान कर की जाएगी, अर्थात् उसका जन्म 1 अप्रैल, 1962 से पूर्व का हो।
- सरकार के आदेशानुसार रेल और हवाई यात्रा के दौरान स्थान रिक्त रहने की परिस्थिति में इच्छुक पात्र व्यक्ति, जिन्होंने आवेदन किया था, को अनुमत करने का अधिकार आयुक्त देवस्थान विभाग को होगा।
- तीर्थ यात्रा के लिये जून के द्वितीय सप्ताह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 30 जून तक चलेगी।
- वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में अब 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन यात्रा के दौरान अपने साथ एक सहायक साथ ले जा सकेंगे।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में तीन जल वितरण समितियों का गठन

चर्चा में क्यों ?

15 जून, 2022 को राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अधिशासी अभियंता वाटर कोर्सेज खंड-द्वितीय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के क्षेत्राधिकार में आने वाले जल उपयोक्ता संगमों को शामिल करते हुए तीन जल वितरण समितियों का गठन कर उनके क्षेत्रों का अंकन किया है।

प्रमुख बिंदु

- अधिसूचना के अनुसार आसूतार जल वितरण समिति में जैसलमेर ज़िले की रामगढ़ तहसील के आसूतार वितरिका जल उपयोक्ता संगम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ; आसूतार माइनर जल उपयोक्ता संगम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम; बांडी माइनर जल उपयोक्ता संगम प्रथम, द्वितीय; भाखरी माइनर जल उपयोक्ता संगम; घोटारू माइनर जल उपयोक्ता संगम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ; रामोज माइनर जल उपयोक्ता संगम; चीता माइनर जल उपयोक्ता संगम तथा दोयता माइनर जल उपयोक्ता संगम प्रथम, द्वितीय, तृतीय शामिल होंगे।

नोट :

- इसी प्रकार मीर का तार जल वितरण समिति के तहत रामगढ़ तहसील के दत्तात्रेय माइनर जल उपयोक्ता संगम, दत्तात्रेय सब माइनर जल उपयोक्ता संगम; मीर का तार वितरिका जल उपयोक्ता संगम; जीडीएम-5 जल उपयोक्ता संगम; मनुहार माइनर जल उपयोक्ता संगम; जीडीएम-6 जल उपयोक्ता संगम; नवातला वितरिका जल उपयोक्ता संगम; जीडीएम-7 जल उपयोक्ता संगम एवं एसएस माइनर जल उपयोक्ता संगम शामिल होंगे।
- धनाना जल वितरिका समिति के तहत रामगढ़ तहसील के जीडीएम-8 जल उपयोक्ता संगम; राबलाउ वितरिका जल उपयोक्ता संगम; जीडीएम-9 जल उपयोक्ता संगम; भुवाना वितरिका जल उपयोक्ता संगम; धनाना वितरिका जल उपयोक्ता संगम प्रथम, द्वितीय, तृतीय; सांखला माइनर जल उपयोक्ता संगम; धनाना माइनर जल उपयोक्ता संगम प्रथम, द्वितीय; धनाना सब माइनर जल उपयोक्ता संगम; गुरुकन्या माइनर व सब माइनर जल उपयोक्ता संगम तथा जीडीएम-10 जल उपयोक्ता संगम शामिल किये गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि इन तीनों जल वितरण समितियों के तहत शामिल जल उपयोक्ता संगमों से करीब 60 हज़ार 146 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र लाभान्वित होगा।

भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक व सिल्वर के पूर्ववेक्षण की तैयारी

चर्चा में क्यों ?

15 जून, 2022 को राजस्थान राज्य के माइंस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य के तीन स्थानों पर कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक व सिल्वर की खोज के कार्य के लिये स्थान चिह्नित किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (NMET) के वित्तीय सहयोग से राज्य के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद ज़िलों में खनिजों का राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET) द्वारा यह खोज का कार्य किया जाएगा।
- भीलवाड़ा के देवतलाई में करीब 700 हेक्टेयर में कॉपर एवं गोल्ड; चित्तौड़गढ़ के भागल में करीब 500 हेक्टेयर में कॉपर; भीलवाड़ा के अमरगढ़ में 600 हेक्टेयर में लेड व जिंक; राजसमंद के करौली में 200 हेक्टेयर में कॉपर और राजसमंद के सिंदेसर में करीब 3500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिल्वर, लेड व जिंक के भंडार का खोज कार्य कर खनन के लिये पाँच प्लॉट तैयार किये जाएंगे।
- उन्होंने बताया कि इस कोश से नवाचारों को भी प्रोत्साहन देने के साथ ही विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं के छात्रों की सर्वेक्षण कार्यों में भी भागीदारी तय की जाएगी, ताकि छात्रों को व्यावहारिक अध्ययन का अवसर प्राप्त हो सके।
- उन्होंने बताया कि RSMET को नेशनल एक्सप्लोरेशन एजेंसी का दर्जा दिलवाने के प्रयास किये जाएंगे, ताकि खनिज खोज व खनन कार्य में आरएसएमईटी की विशेषज्ञ संस्था के रुप में राष्ट्रीय पहचान बन सके।
- माइंस के निदेशक के.बी. पंड्या ने बताया कि RSMET के माध्यम से विभागीय प्रयोगशाला व छिद्रेसन विंग को संरचनात्मक साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे राज्य में खनन खोज कार्य को और अधिक गति दी जा सकेगी।

पाँच दिवसीय 'हैंडलूम प्रदर्शनी-कम सेल' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

15 जून, 2022 को राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आरएचडीसी) की ओर से चौमूँ हाउस स्थित कार्यालय में पाँच दिवसीय 'हैंडलूम प्रदर्शनी-कम सेल' का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- आरएचडीसी की सीएमडी नेहा गिरि ने बताया कि पोस्ट कोविड महामारी की समस्याओं से जूझ रहे राज्य के हथकरधा एवं हस्तशिल्प वस्त्र उद्योग को समुचित विपणन प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 15 से 19 जून तक हैंडलूम प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।

नोट :

- उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में उत्पादों के शोकेस व बिक्री की व्यवस्था भी की गई है। प्रदर्शनी में डिजाइनर कोटा डोरिया, जरी की साड़ियाँ, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड साड़ियाँ, कॉटन ड्रेस मटेरियल, बेड शीट्स, कलात्मक दोहर, दरियाँ, कुर्ते, प्लाजो व शर्ट आदि प्रदर्शित व बिक्री की जाएगी।
- इसमें प्रदेश के नेशनल अवार्डी, उत्कृष्ट बुनकरों तथा दस्तकारों के वस्त्र एवं परिधानों का शोकेस किया जाएगा। प्रदर्शनी में उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी जाएगी।

जयपुर में 'आईस्टार्ट राजस्थान' के तहत हुआ 'ड्रोन एक्सपो-2022'

चर्चा में क्यों ?

16 जून, 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के 'आईस्टार्ट राजस्थान' के तहत झालाना सांस्थानिक क्षेत्र स्थित टेक्नो हब में 'ड्रोन एक्सपो-2022' का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक ड्रोन निर्माताओं ने अपने ड्रोन की क्षमताओं का प्रदर्शन किया।

प्रमुख बिंदु

- ड्रोन निर्माताओं में से किसी ने बाढ़ या समुद्र के भीतर आपातकालीन परिस्थितियों में ड्रोन के जीवनरक्षक बनने का प्रदर्शन किया, तो किसी ने आसमान में एरोबेटिक्स दिखाकर सिंचाई और खेती में ड्रोन के मददगार बनने की क्षमताओं को दिखाया।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार इस वर्ष विभिन्न विभागों के लिये एक हज़ार ड्रोन खरीदने की योजना बना रही है।
- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभागीय अधिकारियों को ड्रोन का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
- आयुक्त संदेश नायक ने किसानों के लिये ड्रोन तकनीक के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ड्रोन न केवल सिंचाई और कीटनाशक छिड़काव में काश्तकारों की मदद कर सकते हैं, बल्कि प्रतिकूल मौसम और परिस्थितियों के कारण होने वाले नुकसान व हानि का सर्वेक्षण करने में भी कृषि विभाग के लिये मददगार बनेंगे।
- उन्होंने कहा कि ड्रोन निगरानी और सुरक्षा में पुलिस विभाग, जल संसाधन विभाग, वन्यजीव व अन्य विभागों की मदद कर सकते हैं।
- उल्लेखनीय है कि 'आईस्टार्ट राजस्थान' प्रदेश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राज्य सरकार की प्रमुख योजना है, जहाँ वर्तमान में 1700 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं और 200 स्टार्टअप इनक्यूबेट हैं। राज्य सरकार की ओर से 300 से अधिक स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।
- विभाग ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार करने के लिये नीति आयोग, एचडीएफसी बैंक, पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और फिक्की एफएलओ, आईसीआईसीआई बैंक, अमेजॉन (एडब्ल्यूएस) के साथ भागीदारी की है।

देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना

चर्चा में क्यों ?

19 जून, 2022 को राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने देशभर में अनूठी एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पशुपालकों के लिये पहली बार तैयार की गई देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना में कब्जा सौंपकर आवंटियों को गृह प्रवेश कराया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से कोटा शहर के पशुपालकों के सुव्यवस्थित शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु देवनारायण एकीकृत आवास योजना विकसित करने की घोषणा की गई थी।
- परियोजना की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा 17 अगस्त, 2020 को रखी गई थी, जिसमें नगर विकास न्यास कोटा द्वारा प्रथम चरण में 738 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 501 आवासों का आवंटन किया गया है।

नोट :

- योजना में पशुपालकों के लिये 1227 बड़े आवासीय भूखंडों का प्रावधान किया गया है। इनमें से 738 आवासों का निर्माण पूर्णकर 501 पशुपालकों को आवंटन कर दिया गया है। इन भूखंडों के पिछले भाग में लगभग 40 वर्ग मीटर क्षेत्र में दो कमरे, रसोईघर, शौचालय, स्नानघर, बरामदा, चारा भंडारण की सुविधा है। भूखंड के अग्रभाग में पशुओं के लिए शेड का निर्माण किया गया है।
- पशुपालकों की सुविधा के लिये योजना में विद्यालय भवन, पशु चिकित्सालय, सोसाइटी कार्यालय, पुलिस चौकी, विद्युत सब स्टेशन, पेयजल के लिए उच्च जलाशय, सीवर लाइन, पार्क, नाली, सड़कें, एसटीपी, पशुमेला मैदान एवं दुग्ध मंडी का भी निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त भविष्य की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, रंगमंच का निर्माण किया गया है।
- योजना में लगभग 15 हजार पशुओं से प्राप्त गोबर के निस्तारण के लिए नगर विकास न्यास द्वारा बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जा रही है जिससे गोबर के निस्तारण के साथ-साथ जैविक खाद का भी उत्पादन होगा।

राजस्थान के नये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

चर्चा में क्यों ?

19 जनवरी, 2022 को केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति शिंदे संभाजी शिवाजी की राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार ने नये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के एक महीने के भीतर मंज़ूरी दी गई है।
- गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
- मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
- वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। हालाँकि, न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से शुरू किया जाता है।

राजस्थान में लव-कुश वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से होगा आरंभ

चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2022 को राजस्थान वन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में लगभग 2-2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लव-कुश वाटिकाओं के निर्माण कार्य की शुरुआत 1 जुलाई, 2022 से की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- इन वाटिकाओं के निर्माण का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करना तथा उनमें वनानुभव को बढ़ावा देना है।
- अग्रवाल ने बताया कि इन वाटिकाओं में स्थानीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अनुकूल वहाँ की स्थानीय वनस्पतियाँ, जैसे- फल, फूल, औषधीय एवं छायादार पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को वहाँ का स्थानीय वनानुभव मिले सके।
- वहीं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख डॉ. डी.एन. पांडेय ने लव-कुश वाटिकाओं के निर्माण की संरचना एवं आकार-प्रकार के बारे में ज़िला उप-वन संरक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि इनके निर्माणकार्य में अधिक-से-अधिक प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाए, ताकि यह लोगों को प्रकृति का अहसास कराने वाली वाटिका साबित हो।

नोट :

सौर कृषि आजीविका योजना (स्काय) के अंतर्गत 1 लाख सोलर पंप होंगे स्थापित

चर्चा में क्यों ?

22 जून, 2022 को राजस्थान की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने प्रधानमंत्री कुसुम-कंपोनेंट-सी (फीडर लेवल सोलराइज़ेशन) के तहत सौर कृषि आजीविका योजना (स्काय) पर आयोजित समीक्षा बैठक में योजना के अंतर्गत 1 लाख सोलर पंप स्थापित करने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ने योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये 33/11 केवी जीएसएस की प्रस्तावित संख्या को 80 से और अधिक बढ़ाने के निर्देश भी दिये।
- बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर आत्माराम सावंत ने बताया कि प्रस्तावित स्काय योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये एक पोर्टल शीघ्र शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से पंजीकरण कर किसान अपनी ज़मीन को जीएसएस स्थापित करने हेतु 25 साल तक के लिये लीज किराए पर दे सकेंगे।
- उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक विकासकर्त्ता भी ज़मीन का चयन कर सकेंगे और सोलर ऊर्जा प्लांट का निर्माण कर सकेंगे। टोंक में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4.24 मेगावाट का कार्य अवार्ड किया गया है, जिसके तहत 656 किसानों को सोलर ऊर्जा मिलेगी।
- स्काय योजना के प्रमुख फीचर्स हैं-
  - किसान को ज़मीन के लिये आकर्षक लीज़ मनी दी जाएगी।
  - किसानों को 8 लाख रुपए तक की ज़मीन (डीएलसी रेट के अनुसार) पर 80 हज़ार रुपए प्रति हेक्टेयर वार्षिक लीज़ किराया।
  - 20 लाख रुपए से अधिक की ज़मीन पर 1 लाख 60 हज़ार रुपए तक का प्रति हेक्टेयर लीज़ किराया।
  - हर दो साल में लीज़ किराया में 5 प्रतिशत की वृद्धि।

1 जुलाई से राजकीय कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएँ प्रतिबंधित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने सभी राजकीय कार्यालयों में 1 जुलाई से एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि प्रतिबंधित वस्तुओं में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक/थर्माकोल (पॉलीस्टाइरीन) डिस्पोजेबल कटलरी, जैसे- कटोरे, ट्रे, कंटेनर आदि, जिनका उपयोग खाने योग्य/पेय परोसने के लिये किया जाता है तथा कृत्रिम फूल, बैनर, झंडे, फूलदान व पेट बोतलें शामिल हैं।
- आदेश में बताया गया है कि कोई भी सरकारी कार्यालय उपर्युक्त एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा और कंपोस्टेबल प्लास्टिक, बायो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़े, पुनर्चक्रित कागज़ सामग्री आदि जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकता है, जिनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है।
- विभाग ने वर्तमान आदेश पूर्व में लागू किये गए नियमों के क्रम में जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2016 को पर्यावरण को अनुकूल तरीके से प्लास्टिक के प्रबंधन के लिये अधिसूचित किया गया है।
- इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिये राज्य सरकार ने 21 जुलाई, 2010 को राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 12 अगस्त, 2021 को एक अधिसूचना जारी कर निर्धारित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित कर दिया है।

नोट :

जोधपुर व डूँगरपुर ज़िले के 1-1 राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर

चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर और डूँगरपुर ज़िले के 1-1 राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर ज़िले की सैखाला पंचायत समिति के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, गिलाकौर का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्व. श्री मंगल सिंह के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
- इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने डूँगरपुर ज़िले की झौथरी पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करावाड़ा का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्व. श्री धुलजी भाई वर्मा के नाम पर करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले वीर सेनानियों के त्याग, बलिदान, संघर्ष एवं जीवन आदर्शों से युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सकेगी।

एमएसएमई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये करौली ज़िले को मिला देश में दूसरा स्थान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड-2022 में राजस्थान के करौली ज़िले को 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट' की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के उप-निदेशक जनरल डी.पी. श्रीवास्तव ने करौली ज़िला कलेक्टर को पत्र के माध्यम से यह सूचना देते हुए बताया कि ज़िले को यह अवार्ड एमएसएमई सेक्टर के विकास तथा प्रमोशन में बेहतरीन योगदान देने के लिये दिया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत यह पुरस्कार जल्द ही एक समारोह आयोजित कर दिया जाएगा।
- गौरतलब है कि राज्य के सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर और करौली ज़िलों को 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट' कार्यक्रम के तहत चयन किया जा चुका है, जिनमें से करौली ज़िले ने बेहतरीन कार्य के लिये दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
- 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स' कार्यक्रम भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसके ज़रिये देश के प्रगतिशील ज़िलों को क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय कार्य के लिये सम्मानित किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार उद्यमिता (विनिर्माण और सेवा), उत्पाद की गुणवत्ता, नवाचार, निर्यात और विनिर्माण तकनीकों के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने के लिये 1983 में स्थापित किये गए थे।
- राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को अपने लेटर हेड में पुरस्कार के प्रतीक चिह्न का उपयोग करने का अधिकार मिलता और उनके कर्मचारी इस प्रतीक चिह्न वाले लेबल, पिन, टाई या अन्य विशिष्ट तरह के बैज पहन सकते हैं।

प्रशासन शहरों के संग अभियान

चर्चा में क्यों ?

23 जून, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'प्रशासन शहरों के संग अभियान' की समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश के सभी नगर निकायों में इस अभियान के शिविर 15 जुलाई से वार्डवार लगेंगे।

प्रमुख बिंदु

- इनमें मौके पर ही सभी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करते हुए पट्टों का वितरण किया जाएगा।

नोट :

- अभियान शुरू करने से पूर्व नगर निकायों के पार्षदों के लिये कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँगी, जिनमें उन्हें अभियान की संपूर्ण जानकारी के साथ नए प्रारूप और राज्य सरकार द्वारा किये गए सरलीकरण और छूटों की जानकारी से अवगत कराया जाएगा, ताकि पार्षद अपने क्षेत्र के लोगों को पट्टे दिलाने में मदद कर सकें।
- नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने प्रस्तुतीकरण देते हुए अभियान के दौरान जारी किये गए पट्टों सहित अन्य कार्यों के बारे में बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 के तहत 3 लाख 36 हज़ार 61 पट्टे जारी किये जा चुके हैं।

'मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना'

चर्चा में क्यों ?

23 जून, 2022 को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में कक्षा एक से 8वीं तक के बच्चों को 'मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना' के तहत सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् करीब 69 लाख 21 हज़ार बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इन दिनों में अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा एक से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा।
- गौरतलब है कि इस योजना की घोषणा वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में की गई थी। इस योजना के लागू होने से कक्षा एक से 8वीं तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होने के साथ ही राजकीय विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों का ड्रॉपआउट भी रुक सकेगा।
- इसके लिये पाउडर मिल्क की खरीद राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से की जाएगी तथा मिड-डे मील आयुक्तालय के माध्यम से पाउडर मिल्क का ज़िलेवार आवंटन किया जाएगा। आरसीडीएफ द्वारा ही आवंटन के अनुसार विद्यालयों तक पाउडर मिल्क की डोर स्टेप डिलिवरी की जाएगी।

ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को मिलेंगे रिप्स-2019 के लाभ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 के लाभ दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टांप ड्यूटी में छूट का लाभ रिप्स-2019 के अंतर्गत मिल सकेगा। रिप्स-2019 के अंतर्गत परिभाषित पर्यटन सेक्टर की इकाइयों में ग्रामीण पर्यटन इकाई को भी परिभाषित किया जाएगा।
- ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स-2019 का पूर्ण लाभ प्रदान किये जाने के लिये इनके निवेश की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रुपए रखा जा सकेगा। साथ ही, देय एवं जमा एसजीएसटी का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण भी हो सकेगा।
- मुख्यमंत्री के इस अनुमोदन से गाँवों में पर्यटन इकाइयों के ज़रिये नए रोज़गार सृजित होंगे, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राजस्थान की ग्रामीण परंपरा से पर्यटक रूबरू हो सकेंगे। गौरतलब है कि पर्यटन उद्योग को रिप्स-2019 के तहत थ्रस्ट सेक्टर का दर्ज़ा भी दिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 की घोषणा की थी।

नोट :

यूरेनियम खनन के क्षेत्र में राजस्थान का प्रवेश

चर्चा में क्यों ?

26 जून, 2022 को राज्य में यूरेनियम उत्खनन के लिये लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी करने के साथ ही राजस्थान यूरेनियम खनन के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह एलओआई सीकर के पास खंडेला तहसील के रोहिल में यूरेनियम अयस्क के खनन के लिये यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टा हेतु ज़ारी किया गया है।
- गौरतलब है कि सीकर ज़िले की खंडेला तहसील के रोहिल में 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम के विपुल भंडार मिले हैं। आरंभिक अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार संभावित हैं।
- देश में अभी झारखंड के सिंहभूमि के जादूगोडा और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का उत्खनन किया जा रहा है।
- वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कज़ाखस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसके अलावा रूस, नामीबिया, उज़्बेकिस्तान, यूएसए व यूक्रेन में भी यूरेनियम खनिज मिला है।
- यूरेनियम का उपयोग मुख्यत: बिजली बनाने में किया जाता है। हालाँकि, परमाणु ऊर्जा के अलावा दवा, रक्षा उपकरणों, फोटोग्राफी सहित अन्य में भी यूरेनियम का उपयोग किया जाता है।

मिशन बुनियाद'

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2022 को राजस्थान की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने डिजिटल शिक्षा पर आधारित 'मिशन बुनियाद' कार्यक्रम को प्रदेश के सभी ज़िलों में लागू करने के संबंध में चिल्ड्रन्स इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (सीईईएफ) को संशोधित प्रस्ताव पर कार्य करने के निर्देश दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में 'मिशन बुनियाद' का संचालन राज्य के 6 ज़िलों- भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही व उदयपुर में किया जा रहा है।
- ऊषा शर्मा ने (सीईईएफ) फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को इस संबंध में प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये हैं, जिससे कार्यक्रम को शीघ्र राज्य के सभी 33 ज़िलों में संचालित किया जा सके।
- इस मिशन के अंतर्गत आठवीं से बारहवीं तक की छात्राओं को अध्ययन करने हेतु टैबलेट दिये जा रहे हैं।
- गौरतलब है कि एक रिसर्च के अनुसार टैबलेट का उपयोग करने से छात्राओं के सीखने के स्तर में 20 प्रतिशत सुधार आया है।

फेस्टिवल ऑफ इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ राजस्थान

चर्चा में क्यों ?

28 जून, 2022 को राजस्थान की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा की अध्यक्षता में हुई स्टेट इनोवेशन काउंसिल की समिति की बैठक में राज्य में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के अवसर पर 'फेस्टिवल ऑफ इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ राजस्थान' आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में नवाचारों को बढ़ावा देने और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शो-केस करने के उद्देश्य से प्रदेश के ज़िलों में होने वाले सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को हर वर्ष 15 अगस्त एवं 26 जनवरी पर सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया।
- मुख्य सचिव ने राज्य में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिये समुचित बजट उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये।

नोट :

- ज़िलों में नवाचारों को प्रोत्साहित करने तथा श्रेष्ठ नवाचारों को चिह्नित करने के लिये पत्र भी लिखा गया है, ताकि प्रदेश इनोवेशन के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ सके।
- गौरतलब है कि राज्य में कृषि, पशुपालन, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों में नवाचारों की काफी संभावनाएँ मौज़ूद हैं।

राजस्थान में बनेगी नई युवा नीति

चर्चा में क्यों ?

29 जून, 2022 को राजस्थान के युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना और राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा ने कौशल खेल और कला-संस्कृति को फोकस करते हुए राज्य में नई युवा नीति बनाए जाने की जानकारी दी।

प्रमुख बिंदु

- इस नई युवा नीति को युवाओं से ब्लॉक स्तर तक संवाद करके तथा इस संवाद में मिलने वाले फीडबैक को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर उसके आधार पर बनाया जाएगा।
- खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर पैदा करना वर्तमान मां सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसके लिये युवाओं में कौशल विकास कर उन्हें रोज़गार से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- खेलों के माध्यम से भी युवाओं में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। राज्य की छुपी हुई कलाओं को उभारकर युवाओं को सशक्त बनाने में मदद की जा सकती है।
- इसलिये इन्हीं तीनों विधाओं पर विशेष फोकस करते हुए यूथ बोर्ड के माध्यम से नई युवा नीति को मूर्त रूप दिया जाएगा।
- चांदना ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं को नशे की बुराई से बचाने के लिये 'नशा मुक्ति' अभियान चलाया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि उद्योगों में राज्य के युवाओं को प्राथमिकता से रोज़गार दिलाने की संभावना पर भी विचार किया जाएगा।
- उन्होंने राज्य में खेलों के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि खेल सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया गया है और ग्रामीण ओलंपिक खेल के रूप में अनूठी पहल की गई है।
- राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी बजट युवाकेंद्रित बनाने की घोषणा की है, जो अच्छी पहल है।
- उन्होंने कहा कि युवा बोर्ड युवाओं के लिये उनकी पसंद की युवा नीति बनवाने पर कार्य कर रहा है। इसके लिये संभाग स्तर और अधिकतर ज़िलों में संवाद कार्यक्रम किये गए हैं, जिनमें हज़ारों युवाओं से इंट्रेक्शन किया गया है।

नोट :